an>

Title: Need to open more paddy purchase centres and pay the arrears to the farmers of Bihar.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र बक्सर, शाहबाद सहित बिहार के विभिन्न जिले जहां धान की अधिकतम पैदावार होती है, वहां के किसानों के साथ राज्य सरकार के सौतेले रवैये के कारण धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है। पिछले एक माह से धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है किन्तु अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is a State matter.

श्री अश्विनी कुमार चौबे : नहीं महोदया। हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में पिछले दिनों किसानों की महापंचायत लगी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था। जब प्रत्येक पंचायत में मतदान केन्द्र हो सकते हैं तो धान क्रय केन्द्र क्यों नहीं हो सकता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र बक्सर, शाहबाद सहित बिहार के विभिन्न जिले जहां धान की अधिकतम पैदावार होती है, वहां के किसानों के साथ राज्य सरकार के सौतेले रवैये के कारण धान क्रय केन्द्र नहीं खुल पाया है। पिछले एक माह से धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है, किन्तु अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है।...(व्यवधान) हमारे संसदीय क्षेत्र दिनारा (सासाराम) में विगत 22 नवम्बर, 2015 को हम लोगों ने धान क्रय हेतु किसान महापंचायत लगाई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी पंचायतों में यदि मतदान केन्द्र हो सकते हैं तो किसानों के हित में धान क्रय केन्द्र क्यों नहीं खोले जा सकते हैं? किसानों के हित में यह काम आवश्यक है, पिछले वर्ष का भी भुगतान राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, जिससे किसान आत्महत्या, भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, बिचौलियों के द्वारा धान को औने-पौने दाम पर क्रय किया जा रहा है। किसानों के धान का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष का करीब 200 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अभी तक डीजल अनुदान राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है। बिहार राज्य को छोड़कर सभी राज्य जहां धान की फसल अधिक होती है, वहां राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई है लेकिन बिहार सरकार अभी भी कुंभकरणी निंद्रा में सोई हुई है। किसान तड़प -तड़प कर मर रहे हैं और राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के विभिन्न जिलों में पंचायत स्तर पर धान क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाए, साथ ही पिछले वर्ष के बकाये राशि का भी भुगतान किया जाए और भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाए। हाल में बिहार सरकार ने प्रति किसान के लिए 100 क्विंटल धान क्रय करने की व्यवस्था की है जो सर्वथा अनुचित है। किसानों के लिए उनके ऊपज के आधार पर धान क्रय करना सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 300 रुपये बोनस के बदले 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करना चाहए चाहिए। साथ ही, केंद्र सरकार को भी बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए धान/रबी के समर्थन मूल्य को बढ़ाने हेतु गंभीरता से विचार करना चाहिए।

HON. SPEAKER:

Shri Bharon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ashwini Kumar Chaubey.